भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2851
(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

डिजिटल ग्राम परियोजना

2851. श्री मलैयारासन डी.:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में उन गांवों की संख्या कितनी है जहाँ डिजिटल ग्राम परियोजना योजनाबद्ध रूप में सभी डिजिटल सुविधाओं सहित पूर्ण रूप से संचालित है;
(ख) सभी निवासियों के लिए पर्याप्त इंटरनेट बैंडविड्थ, विद्युत और डिजिटल उपकरणों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ग) क्या महिलाओं, छात्रों और वंचित समूहों के लिए डिजिटल सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विशेष पहल की गईं हैं; और
(घ) कनेक्टिविटी या संसाधनों की कमी का सामना कर रहे गांवों में डिजिटल विभाजन (डिजिटल डिवाइड) और अवसंरचना के अंतराल को दूर करने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ) दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के उन दूरस्थ एवं ग्रामीण गांवों तथा द्वीपों में, जहां वर्तमान में नेटवर्क कवरेज का अभाव है, उच्च बैंडविड्थ क्षमता वाली इंटरनेट/ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) [पूर्ववर्ती सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ)], दूरसंचार विभाग द्वारा वित्तपोषित अनेक कदम उठाए गए हैं तथा परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। फरवरी 2026 तक, देश में भारतनेट परियोजना के अंतर्गत लगभग 2,17,805 ग्राम पंचायतों को सेवा-सक्षम बनाया जा चुका है, जिनमें तमिलनाडु की 10,886 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा दिनांक 04.08.2023 को अनुमोदित संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को भारतनेट चरण-I और चरण-II के विद्यमान नेटवर्क के

उन्नयन, शेष ग्राम पंचायतों में नेटवर्क उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा मांग के आधार पर शेष गैर-ग्राम पंचायत गांवों तक कनेक्टिविटी विस्तार के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

4जी संतृप्ति परियोजना और अन्य मोबाइल परियोजनाओं के अंतर्गत, फरवरी 2026 तक देश के अनकवर्ड दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 24,263 मोबाइल टावर कार्यान्वित किए जा चुके हैं। चेन्नई और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बीच (2312 किमी) तथा मुख्य भूमि (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच (1869 किमी) सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के कार्यकरण एवं लक्षद्वीप द्वीप समूह में एफटीएचएच व अन्य सेवाओं की प्रदायगी हेतु 225 किमी ओएफसी नेटवर्क के निर्माण से द्वीपों में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड/इंटरनेट सेवाओं, मोबाइल सेवाओं (4जी/5जी) तथा अन्य हाई-स्पीड डेटा सेवाओं के त्वरित विस्तार में सुविधा हुई है।

ग्रामीण विकास विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सीडीएसी) और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआईसी) के सहयोग से अपनी प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न आईटी-आधारित समाधान डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित किए हैं। डिजिटल विभाजन को कम करने और अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, ग्राम पंचायत स्तर पर सेवाएं प्रदान करने वाले डिजिटल सुशासन समाधानों को ऑफलाइन क्षमताओं, दिव्यांगजन-अनुकूल प्लेटफार्मों तथा बहुभाषी सुविधाओं के साथ सरल उपयोगकर्ता इंटरफेस के साथ विकसित किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि इन समाधानों तक पहुंच केवल इंटरनेट से जुड़े क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है बल्कि दूरस्थ या संपर्कता रहित क्षेत्रों में भी उपलब्ध है।